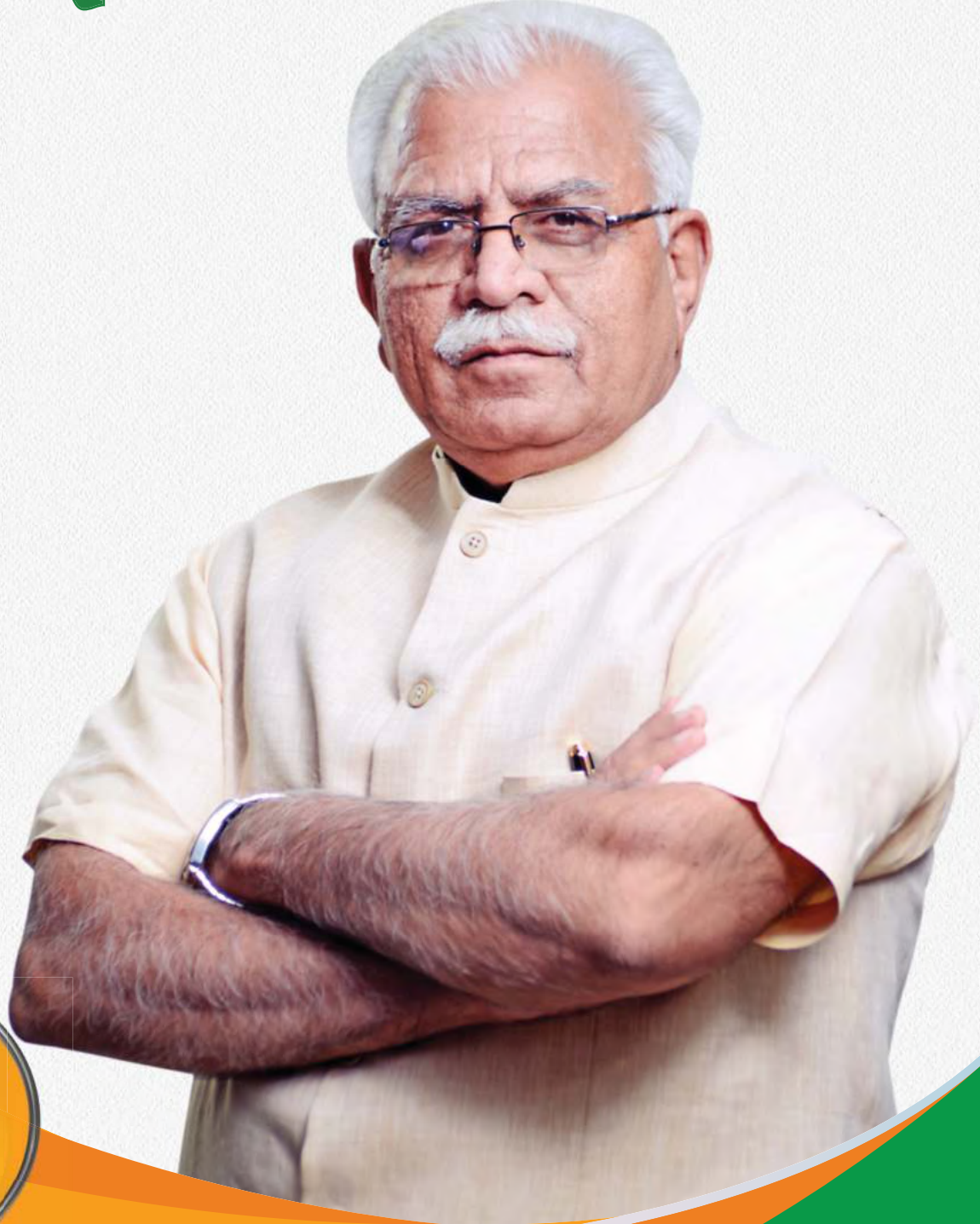
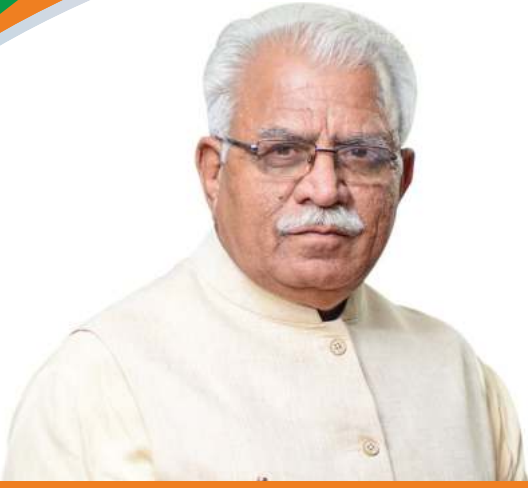


# साप्ताहिक सूचना पत्र



भारतीय जनता पार्टी  
हरियाणा



# साप्ताहिक सूचना पत्र

## हाई पॉवर परचेज कमेटी मीटिंग

(दिनांक 12.06.21)



**विषय:** हाई पॉवर परचेज कमेटी की मीटिंग।

**निर्णय:** आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में HPPC की मीटिंग हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और खरीद को मंजूरी दी गई। इसमें :-

- हरियाणा रोडवेज के लिए 800 नई बसें खरीदना।
- बिजली विभाग के लिए ट्रांसफार्मर और नई लाइन बिछाने का काम शामिल है इसके साथ ही मीटिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया जिसके तहत इस साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को पाठ्य पुस्तक की जगह पाठ्य पुस्तक का पैसा उनके

अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। यह निर्णय कोरोना के चलते स्कूलों के बंद होने और ऑनलाइन क्लासेज चलने के कारण लिया गया।

## वॉटर अथॉरिटी की मीटिंग

(दिनांक 13.06.21)

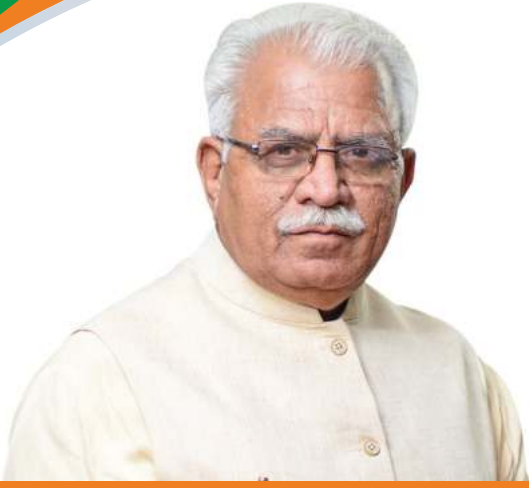
**विषय:** वॉटर अथॉरिटी की मीटिंग।

**निर्णय:** आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हरियाणा वॉटर अथॉरिटी की पहली मीटिंग हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि :-

- हरियाणा में माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पूरे हरियाणा का एक वाटर मैप तैयार किया जाएगा। जिसके आधार पर पता लग सके कहां पानी की कितनी कमी है।
- ट्रीटेड पानी को इण्डस्ट्री और इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

- वाटर लॉगिंग एरिया में ग्राउंड वाटर रिचार्ज का सिस्टम बनाया जाएगा।





# साप्ताहिक सूचना पत्र

## वन विभाग की समीक्षा बैठक

(दिनांक 14.06.21)

**विषय:** वन विभाग की समीक्षा बैठक।

**निर्णय:** माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-

- हरियाणा की कुल भूमि के 20 प्रतिशत भाग पर वन लगाए जाएंगे। इसके लिए इसे पहले 20 वर्ष में 10 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- वन विभाग द्वारा लगाए गए सभी पौधों की जीओ टैगिंग की जाएगी जिससे उनकी निगरानी करने और देखभाल करने में आसानी होगी।



- पुराने और वृद्ध पेड़ों को छांटकर उनका संरक्षण किया जाएगा और उन्हें पेंशन दी जाएगी।

इस अवसर पर वन विभाग द्वारा 'E-पौधशाला' नामक एप्प का भी उद्घाटन किया गया जिसकी सहायता से हरियाणा का कोई भी व्यक्ति वन विभाग की नर्सरी से निःशुल्क पौधों को ले सकेगा और उन्हें लगा सकेगा।

## पंचायती राज और लोकल बॉडी फंडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम

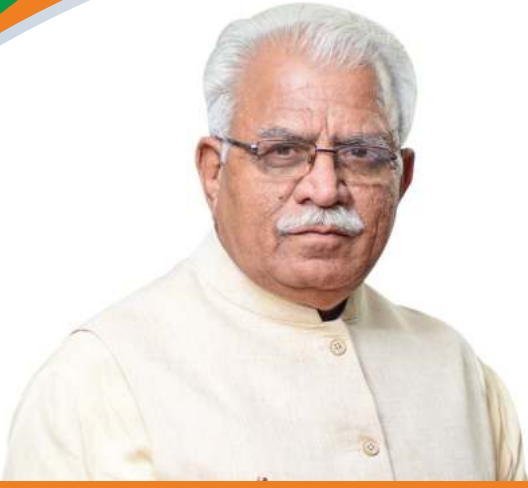
(दिनांक 14.06.21)

**विषय:** पंचायती राज और लोकल बॉडी फंडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम।

**प्रभाव:** आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पंचायती राज और सभी लोगों को राज्य और केन्द्र की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। इसकी मदद से :-

- पंचायती राज और नगरीय निकाय संस्थाओं को समय पर पैसा (अनुदान राशि) मिल सकेगी।
- अनुदान राशि देने में समानता और पारदर्शिता आएगी।
- संस्थाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सकेगा।
- संस्थाओं द्वारा किए गए खर्च और कार्य की समीक्षा व निगरानी की जा सकेगी।
- सभी संस्थाओं को अपनी आमदन और खर्च इस पोर्टल पर चढाना अनिवार्य होगा।





# साप्ताहिक सूचना पत्र

## पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विडियो कांफ्रेंस (दिनांक 14.06.21)

**विषय:** पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विडियो कांफ्रेंस।

**प्रभाव:** माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आगामी कार्यक्रमों और कार्यों को लेकर संगठन व पार्टी द्वारा आयोजित विडियो कांफ्रेंस में भाग लिया गया। इसमें संगठन मंत्री हरियाणा के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के कई विधायक, सांसद और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से होने वाले कार्यक्रमों में पूरी निष्ठा से काम करने के साथ पौधारोपण और परिवार पहचान पत्र को भी लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ाने का आवहान किया गया।



## कैबिनेट मीटिंग (दिनांक 15.06.21)

**विषय:** कैबिनेट मीटिंग।

**प्रभाव:** आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें :-

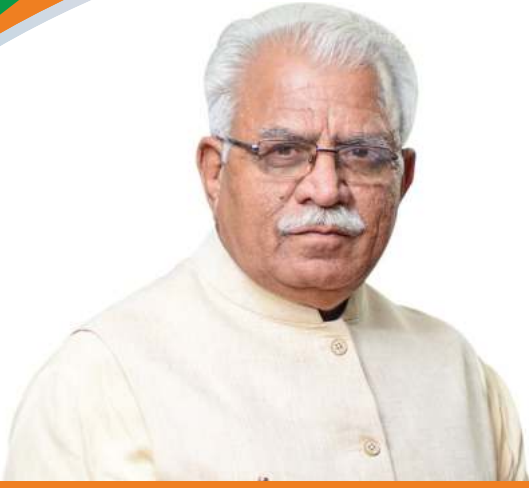
- हरियाणा लोक सेवा आयोग की 3 सीटें कम करके 5 सदस्यीय किया गया।
- निराश्रित बच्चों/महिलाओं की पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
- हरियाणा में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ाते हुए नए उपभोक्ता



संरक्षण नियम 2021 को बनाने की मंजूरी दी गई।

- जिन लोगों और संस्थाओं ने कोरोना राहत के दौरान उपकरण और अन्य सामग्री की है उन्हें इस पर लगने वाली GST लौटाई जाएगी।
- अब कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी सीधा शोरूम पर ही होगा इससे भ्रष्टाचार को कम करने और RTA में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।





# साप्ताहिक सूचना पत्र

## गौ-सेवा आयोग मीटिंग (दिनांक 16.06.21)

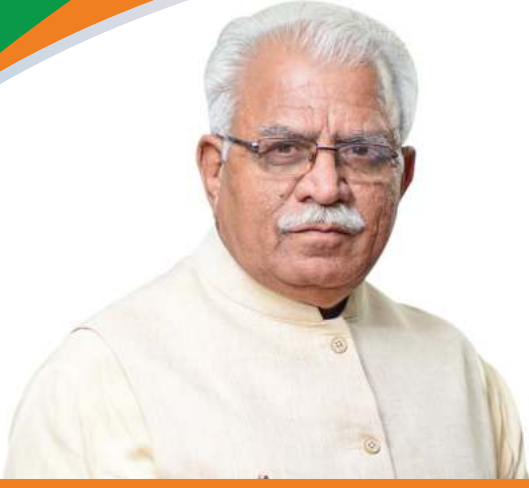


### विषय: गौ-सेवा आयोग की मीटिंग ।

**निर्णय:** आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गौ-सेवा आयोग की मीटिंग ली गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें :-

- आवारा पशुओं को रखने वाली गो-शालाओं को ग्रांट दी जाएगी ।
- गौ-सेवा आयोग के 50 करोड बजट का 30 करोड रुपया चारे के लिए और 20 करोड रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जा सकेगा ।
- घायल और बीमार गायों की देख रेख के लिए पशु चिकित्सालय या गौ शालाओ में ही रख रखाव की व्यवस्था की जाएगी ।
- 50 लाख रू तक की ग्रांट देने की पावर चेयरमेन की होगी जो अतिआवश्यक स्थिति में गौ-शालाओ को दे सकेगा ।
- सभी पशुओं को टेगिंग के लिए चिप के माध्यम से टेगिंग की जाएगी इसका पायलट प्रोजेक्ट पंचकूला जिले में किया जाएगा ।





# साप्ताहिक सूचना पत्र

## सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर प्रेस काफ़ेंस (दिनांक 17.06.21)



**विषय:** सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर प्रेस काफ़ेंस।

**प्रभाव:** आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर प्रेस काफ़ेंस की गई जिसमें सरकार की उपलब्धियों और कोरोना से लड़ाई की तैयारियों और राहत पैकेज की जानकारी प्रदेश को दी गई इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा :-

- कोरोना राहत पैकेज के रूप में 1100 करोड़ रु की घोषणा की। जिसके तहत कोरोना में अपना को खोने वाले परिवार को 2 लाख, होम आइसोलेशन में रहे लोगो को 5000 और गरीब व छोटे दुकानदारों कारीगरों को 5000 रुपये देने के साथ बी.पी.एल परिवार वालो का पूरा खर्च उठाने की योजना शामिल है।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने सरकार की अनेक योजनाओं में मेरा पानी मेरी विरासत, परिवार पहचान पत्र, लाल डोरा मुक्त, सम्पति का मालिकाना हक आदि की जानकारी भी लोगो को दी।
- साथ ही कोरोना से जान गवाने वाले लोगो को 2 लाख और होम आइसोलेशन वाले लोगो को 5000 रु की सहायता राशि उनके खाते में ट्रांसफर की।

## दिल्ली प्रवास

(दिनांक 18.06.21)

**विषय:** दिल्ली प्रवास

**प्रभाव:** माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों से संबंधित प्रोजेक्ट ओर योजनाओं के संबंध में दो दिवसिय दिल्ली का दौरा किया जिसमें उन्होंने विभिन्न विभागों के केन्द्रीय मंत्रियों से मिलकर हरियाणा में चल रहे प्रोजेक्ट और योजनाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह किया और उन पर आ रही रुकावटों पर चर्चा की। इसमें पर्यावरण मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री, पॉवर मिनिस्ट्री आदि विभाग शामिल रहे।

